शहरी समाचार
नई सोच नई पहल

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार का प्रकाशन

सितंबर, 2021 | मासिक | 11वाँ अंक | नगरीय बुलेटिन | पृष्ठ :12 | मूल्यः निःशुल्क

प्रधान मंत्री आवास योजना–शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

DAY-NULM
Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission

आत्मनिर्भर भारत

प्रमुख आलेख

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगरीय प्रशासन निदेशालय व जेएसएलपीएस के बीच हुआ महत्वपूर्ण करार (MoU)

ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध होंगे 'सोनचिरैया' ब्रांड के प्रोडक्ट

स्वतंत्रता दिवस पर गृह प्रवेश के साथ पीएम आवास के लाभुकों ने मनाया आजादी का जश्न

12,837	**77,401**	**23,825**	**29,315**
स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन	PMAY(U) आवासों का निर्माण पूर्ण	पीएम स्वनिधि ऋण वितरित	मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) जॉब कार्ड वितरित

इस अंक में

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगरीय प्रशासन निदेशालय व जेएसएलपीएस के बीच हुआ महत्वपूर्ण करार **(MoU)**

डे-एनयूएलएम योजना के सामुदायिक संसाधन सेवियों के तीन दिवसीय आवासीय उन्मुखीकरण सह स्क्रीनिंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य भर में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजना

'चलंत दुकान' से लोगों को मिल रहा जरूरत का हर सामान

राज्य भर के नगर निकायों में हुआ 'मुख्यमंत्री श्रमिक योजना दिवस' का आयोजन

असहाइ आर बेबस रूपमणि के मिललइ मुख्यमंत्री श्रमिक योजना से जीएक सहारा

जेएनएसी की नई पहल : प्रदूषणमुक्त होगा जमशेदपुर शहर

ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध होंगे 'सोनचिरैया' ब्रांड के प्रोडक्ट

स्वतंत्रता दिवस पर गृह प्रवेश के साथ पीएम आवास के लाभुकों ने मनाया आजादी का जश्न

पीएम आवास योजना के तहत कुष्ठ रोगियों को जल्द मिलेगा अपना आशियाना

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना **(MSY)** से बदल रही हजारीबाग शहर की तस्वीर

PM आवास योजना के तहत **25,000** रुपये जीतने का मौका

ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर : गढ़वा नगर परिषद

"आवास पर संवाद" कार्यक्रम के तहत "समावेशी आवास" विषय पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन

संदेश

नगरीय प्रशासन निदेशालय के "शहरी समाचार" का नवीन अंक निदेशालय के न्यूज लेटर की श्रृंखला का ग्यारहवां अंक है। इस न्यूज लेटर के माध्यम से हमने विगत वर्ष 2020 से अनवरत राज्य के सभी स्थानीय निकायों से जुड़ी छोटी-बड़ी गतिविधियों को समाहित करने का प्रयास किया है। "शहरी समाचार" का आगाज कोरोना महामारी के संक्रमण के दौरान ही शुरू हुआ था। वर्तमान में भी पूरी मानव जाति इस वैश्विक महामारी से पूरी तरह निजात नहीं पा सकी है। ऐसे में नगरीय प्रशासन निदेशालय अपने सभी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर अपनी मुख्य भूमिका को पूर्ण करने के साथ-साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए भी संबंधित प्रबंधन का कार्य कर रहा है। कोरोना महामारी की त्रासदी से उत्पन्न कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विगत अगस्त माह निदेशालय व राज्य के सभी नगर निकायों के लिए उपलब्धियों की अवधि साबित हुआ है। "शहरी समाचार" के सितंबर, 2021 के अंक में राज्य के सभी स्थानीय निकायों की प्रमुख गतिविधियां-दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगरीय प्रशासन निदेशालय व जेएसएलपीएस के बीच हुआ महत्वपूर्ण करार, डे-एनयूएलएम योजना के सामुदायिक संसाधन सेवियों के तीन दिवसीय आवासीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्यभर में जनसुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन, राज्यभर के नगर निकायों में हुआ मुख्यमंत्री श्रमिक योजना दिवस का आयोजन, जेएनएसी की नई पहल : प्रदूषणमुक्त होगा जमशेदपुर शहर, असहाइ आर बेबस रूपमणि के मिललई मुख्यमंत्री श्रमिक योजना से जीएक सहारा, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) से बदल रही हजारीबाग शहर की तस्वीर, पीएम आवास योजना के तहत 25,000 रुपये जीतने का मौका, 'आवास पर संवाद' कार्यक्रम के तहत 'समावेशी आवास' विषय पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन, चलंत दुकान से लोगों को मिल रहा जरूरत का हर सामान, ऐतिहासिक व सांस्कतिक धरोहर है गढ़वा शहर आदि से संबंधित अन्य गतिविधियों को समाहित किया गया है। वर्तमान में राज्य में मानसून की जोरदार बारिश होने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की चुनौतियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है, लेकिन बारिश की फुहारों के साथ-साथ सुहावना होता मौसम नई ऊर्जा व उत्साह का संचार भी कर रहा है। इस अवधारणा के साथ मैं अपनी सभी सहयोगी संस्थाओं को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने की अपील करती हूं। साथ ही आशा करती हूं कि "शहरी समाचार" का यह अंक हम सभी के लिए प्रेरणादायक व लाभकारी साबित होगा।

विजया जाधव
निदेशक,
नगरीय प्रशासन निदेशालय।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगरीय प्रशासन निदेशालय व जेएसएलपीएस के बीच हुआ महत्वपूर्ण करार (MoU)

राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की गरीबी दूर करने के लिए होगा सम्मिलित प्रयास

अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में दिनांक 03.08.2021 को नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्वावधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों, कार्यरत CMMs/COs/CRPs के क्षमता वर्धन हेतु नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA), नगर विकास एवं आवास विभाग तथा झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग के बीच एक एकरारनामा (MoU) किया गया। इसके साथ ही नगर मिशन प्रबंधकों के 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास सचिव श्री मनीष रंजन, JSLPS की सीईओ श्रीमती नैन्सी सहाय व डीएमए की निदेशक विजया जाधव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। एकरारनामा (MoU) के तहत झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (JSLPS) नॉलेज पार्टनर के रूप में काम करेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के उपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री विनय कुमार चौबे ने अपने संबोधन में कहा कि आज नगरीय प्रशासन निदेशालय तथा जेएसएलपीएस के बीच हुआ एकरारनामा (MoU) तथा स्वयं सहायता समूहों, कार्यरत सिटी मिशन मैनेजर्स/सीआरपी/कम्युनिटी आर्गनाइजर्स के लिए शुरू हो रहा छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम झारखंड के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना व महिलाओं का उत्थान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मवारी है। वर्तमान में झारखण्ड में 50 से 55 लाख गरीब परिवार हैं। इनमें से स्वयं सहायता समूह 50 प्रतिशत परिवारों को कवर कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सीआरपी दीदी हर जगह गरीब महिलाओं की सहायता के लिए मौजूद हैं। मगर शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों (स्लम एरिया) में रहने वाली गरीब महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए हर जगह सीआरपी दीदी की मौजूदगी व पहुंच अभी तक संभव नहीं हो पाई है। गांवों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह (SHGs) का फीडबैक आज मजबूत स्थिति में है। वे अपने हाथों से विभिन्न सामानों का उत्पादन भी कर रही हैं, मगर उनमें मार्केटिंग स्किल (विपणन कौशल) की कमी है, जिसे विकसित करना वर्तमान समय की मांग है। ऐसे में नगरीय प्रशासन निदेशालय व जेएसएलपीएस दोनों के बीच सामंजस्य हो जाने से एक तरफ जहां जेएसएलपीएस से सिटी मिशन मैनेजर्स को तकनीकी सहायता मिलेगी, वहीं जेएसएलपीएस को भी नगरीय प्रशासन निदेशालय से रिवर्स सपोर्ट मिलेगा। इस मौके पर नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव ने अपने संबोधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों, इससे होने वाले लाभों एवं वर्तमान समस्याओं से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने डे-एनयूलएम के उद्देश्यों व उसके विभिन्न घटकों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि डीएमए एवं जेएसएलपीएस के बीच आज हुआ एकरारनामा (MoU) एवं छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम झारखण्ड की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों का गठन, संवर्धन, सशक्तिकरण, रोजगार सृजन तथा उनके विकास की प्रक्रिया को गति देने में मददगार साबित होगा। इससे राज्य की महिलाएं और ज्यादा सशक्त होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक उत्प्रेरण एवं संस्थान विकास (SM&ID) डे-एनयूएलएम का एक प्रमुख घटक है। डे-एनयूएलएम योजना के तहत झारखण्ड में कार्यरत 50 शहरी नगर निकायों (ULBs) में वर्तमान में 12,355 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन इकाई मजबूत होता है, वहीं उनका विपणन कौशल (Marketing Skill) कमजोर होता है। हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को आर्थिक रूप से और सशक्त करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। जेएसएलपीएस कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसके अनुभव का लाभ योजना के क्रियान्वयन में सभी कर्मियों व सहयोगियों के लिए मददगार साबित होगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब डीएमए एवं जेएसएलपीएस के बीच एक महत्वपूर्ण एकरारनामा (MoU) हो रहा है। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से पूरे समाज का आधार मजबूत होगा।

इस मौके पर जेएसएलपीएस की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) श्रीमती नैन्सी सहाय ने सामाजिक उत्प्रेरण पर और अधिक काम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जेएसएलपीएस झारखंड के सभी जिलों में पूरी सक्रियता के साथ कार्यरत है। नगरीय प्रशासन निदेशालय व जेएसएलपीएस के बीच आज हुए एकरारनामा के उद्देश्यों को हम आपसी सहयोग व समन्वय से पूरा करेंगे और इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है कि छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जेएसएलपीएस तकनीकी सहायता प्रदान कर कार्यक्रम के मकसद को अवश्य पूरा करेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

पहले दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य भर के नगर निकायों से 30 नगर मिशन प्रबंधकों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जेएसएलपीएस नालेज पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 03 से 08 अगस्त तक चलाया गया। भविष्य में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कार्यरत CMMs/CRPs/COs तथा शहरी क्षेत्र के लगभग 12,000 SHGs के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भविष्य में प्रशिक्षण के उपरांत महिला स्वयं सहायता समूहों को क्षमता वर्धन के उपरांत स्वरोजगार एवं व्यवस्था हेतु प्रेरित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम से पहले झारखंड में डे-एनयुएलएम योजना के तहत चल रहे कार्यक्रमों पर बनाई गई एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।

द्वीप प्रज्जवलित करते नगर विकास के सचिव श्री विनय कुमार चौबे।

> झारखण्ड प्रदेश वन आच्छादित क्षेत्र है, इसलिए हमें सतत प्रवाह वाले रास्ते में आगे बढ़ना होगा। उदाहरण के लिए वन उत्पाद जैसे शाल के पत्ते से बने पत्तल के प्लेट आदि के लिए उचित बाजार की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए हमें ग्रामीण समूह की महिलाओं में मार्केटिंग स्किल (विपणन कौशल) विकसित करने पर जोर देना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की गरीबी में कमी आएगी। जेएसएलपीएस के पास कर्मियों का बड़ा समूह है। हमने देखा है कि जेएसएलपीएस ने कोरोना काल में 'दीदी किचन' की शुरुआत कर एक बड़ी आबादी के लिए सराहनीय कार्य किया है।
>
> -**श्री विनय कुमार चौबे**, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग

नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव व जेएसएलपीएस की सीईओ श्रीमती नैन्सी सहाय ने MoU का हस्तांतरण किया।

डे-एनयूएलएम योजना के सामुदायिक संसाधन सेवियों के तीन दिवसीय आवासीय उन्मुखीकरण सह स्क्रीनिंग कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

राज्य के सभी जिलों के सामुदायिक संसाधन सेवियों (CRPs) को क्रमवार दिया जाएगा प्रशिक्षण

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से डे-एनयूएलएम योजना के घटक SM&ID अंतर्गत सामुदायिक संसाधन सेवियों (CRPs) के ''तीन दिवसीय आवासीय उन्मुखीकरण-सह-स्क्रीनिंग कार्यक्रम'' का आयोजन दिनांक 11.08.2021 से 13.08.2021 राजधानी रांची के तीन विभिन्न स्थानों पर किया गया।

होटल रॉयल रांची में कार्यक्रम का उद्घाटन डीएमए के सहायक निदेशक श्री योगेन्द्र प्रसाद ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम डे-एनयूएलएम की नेशनल रिसोर्स पर्सन अन्नू कुमारी व स्टेट रिसोर्स पर्सन रीना मिश्रा की देखरेख में लगातार तीन दिनों तक चला। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण करना, उनका बौद्धिक विकास करना तथा उनमें आपसी समझ विकसित करना था।

उद्घाटन कार्यक्रम की तस्वीर।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से प्रक्रिया आधारित था। इसी के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों का क्षमता संवर्धन किया गया। गौरतलब है कि वर्तमान समय में राज्य में जेएसयूएलडीएस (JSULDS) के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की योजनाओं व कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही गरीब महिलाओं को प्रक्रियाबद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं सहायता समूह गठित करते हुए आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके आर्थिक सशक्तिकरण बनाने की दिशा में भी प्रयास जारी हैं। यह तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसी की एक कड़ी है।

अलग-अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में अब तक 11 बैचों में कुल 364 सामुदायिक संसाधन सेवियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा।

पहला दिन

पहले दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य रूप से 'गरीबी क्या है ? गरीबी की परिभाषा व गरीब कौन है' विषय पर चर्चा के साथ की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में 'गरीबी के मुख्य कारण, गरीबी बढाने वाले कारण व गरीबी हटाने के सात कदम' विषय के अंतर्गत चर्चा की गई। इसके बाद अंतिम सत्र में लिखित, भाषण व शैक्षणिक खेल के माध्यम से समूह क्यों, प्रशिक्षण का केस स्टडी, चार्ट कार्य व अभ्यास से प्रशिक्षणार्थियों को परिचित कराया गया।

कार्यक्रम के प्रथम दिन प्रशिक्षण प्राप्त करते प्रशिक्षणार्थी।

दूसरा दिन

प्रशिक्षण के दूसरे दिन के कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से समूह की परिभाषा, समूह के गठन, समूह गठन में ध्यान देने वाली बातें, समूह के नियम, अच्छे समूह के लक्षण आदि पर चर्चा की गई। इस दौरान खासतौर पर आपसी लेन-देन करने, समय पर पैसा लौटाने, आपसी तालमेल बनाए रखने, समूह की बैठक में दूसरों की बातों को सुनने व ईमानदारी की शर्त को कायम रखने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में प्रशिक्षकों ने समूह का केस स्टडी, साप्ताहिक बैठक का तरीका, चार्ट कार्य एवं अभ्यास पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रशिक्षण प्राप्त करते प्रशिक्षणार्थी।

तीसरा दिन

प्रशिक्षण के तीसरे व अंतिम दिन के कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूह की होनेवाली साप्ताहिक बैठक से लाभ, दस सूत्र, साप्ताहिक बैठक का एजेंडा, पदाधिकारियों का चयन, पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां, एसएचजी पुस्तक के प्रकार, पुस्तक के रख-रखाव पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे व अंतिम सत्र में प्रशिक्षणार्थियों का लिखित परीक्षण किया गया। इसके उपरांत प्रशिक्षण में शामिल सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में डे-एनयूएलएम के पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण की समीक्षा की गई तथा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के तीसरे व अंतिम दिन प्रशिक्षण प्राप्त करते प्रशिक्षणार्थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य भर में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन

योजना के क्रियान्वयन में बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनभागीदारी सुनिश्चित करने का है उद्देश्य

धनबाद नगर निगम

गढ़वा नगर परिषद

लोहरदगा नगर परिषद

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान विभिन्न नगर निकायों में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ।

राज्य के नौ जिलों के नगर निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों का सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए 22 जुलाई से 30 जुलाई तक सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) का कार्य पूरा किया गया।

नगरीय प्रशासन निदेशालय के निर्देशन में शुरू हुए इस कार्य को विभिन्न चरणों में पूरा किया गया। सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य के जिन 9 जिलों के शहरी निकायों का चयन किया गया था, उनमें धनबाद, गढ़वा, बासुकिनाथ, मधुपुर, दुमका, चक्रधरपुर, रामगढ़, सिमडेगा और लोहरदगा शामिल था। सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा PMAY(U) के अंतर्गत विभिन्न वार्डों के लाभुकों का भौतिक निरीक्षण, लाभार्थी सभा, जियो टैगिंग, लाभुक का चयन, किए गए कार्य के विरूद्ध किश्त का भुगतान, कार्य की गुणवत्ता, ग्रीन कार्ड की उपलब्धता, संचिकाओं एवं तकनीकी कार्य आदि की जांच की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निर्माण क्षेत्र में बिजली, पेयजल व शौचालय के साथ-साथ इनकी उपयोगिता की भी समीक्षा की गई। सामाजिक अंकेक्षण के पहले चरण में उन्मुखीकरण कार्यक्रम (Orientation Programme) आयोजित किया गया। इस दौरान लॉटरी के माध्यम से विभिन्न वार्डों का चयन किया गया।

> **जन सुनवाई कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नगरीय प्रशासन निदेशालय के PMAY(U) कोषांग के पदाधिकारियों ने विभिन्न जिलों का दौरा किया।**

चयनित सभी वार्डों में पीएम आवासों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। ऑडिट के लिए लॉटरी से चयनित वार्डों में से प्रत्येक वार्ड से लाभुकों का चयन किया गया जिन्हें अंकेक्षण दल का सदस्य बनाया गया। सामाजिक अंकेक्षण करने वाले दल में जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, योजना के लाभुक व विभिन्न सरकारी समितियों के प्रतिनिधियों के अलावा आम नागरिक भी शामिल थे। सामाजिक स्तर पर तैयार ऑडिट टीम ने सबसे पहले पीएम आवास योजना (शहरी) के लाभुकों से संबंधित संचिकाओं का अध्ययन किया। बाद में तीन दिन तक फील्ड भ्रमण कर आवासों आदि की जांच की गई। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूरा होने के उपरांत अगस्त माह के पहले सप्ताह में सार्वजनिक जन सुनवाई आयोजित की गई।

सामाजिक अंकेक्षण टीम ने पीएम आवास योजना (शहरी) के धरातलीय अध्ययन करने के उपरांत जो निष्कर्ष पाया, उसकी रिपोर्ट को जनसुनवाई कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से रखा गया। सामाजिक अंकेक्षण टीम के सदस्यों द्वारा संबंधित पदाधिकारी से इन्हें शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

'चलंत दुकान' से लोगों को मिल रहा जरूरत का हर सामान

सफलता की कहानी, लाभुक की जुबानी

श्री अनिल कुमार सिन्हा एक मोबाइल स्ट्रीट वेंडर हैं। वह हजारीबाग निगम क्षेत्र में अपनी स्कूटी पर घर-घर जाकर घरेलू सामानों की बिक्री करते हैं। कोरोना की पहली लहर के समय लॉकडाउन के कारण वह बहुत आर्थिक संकट में थे। उन्हें कहीं से भी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही थी।

वह अपने घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं और परिवार के कुल चार सदस्य उन्हीं पर निर्भर हैं। उन्हें नगर निगम, हजारीबाग के डे-एनयूएलएम कर्मचारियों द्वारा पीएम स्वनिधि ऋण के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद अनिल कुमार सिन्हा ने ऑनलाइन ऋण फॉर्म भरा और बैंक व निगम कर्मचारियों की मदद से उन्हें बिना किसी बंधक के 10,000 रुपये का ऋण आसानी से मिल गया। इस राशि से उन्होंने अपने व्यवसाय को फिर से शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने लॉकडाउन के समय भी अच्छी कमाई की। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने, मास्क के उपयोग करने, सेनिटाइज़ करते रहने और घर में ही सुरक्षित रहने का भी संदेश दिया।

उन्होंने डिजिटल भुगतान के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा दिया। अपना रोजगार अच्छी तरह चलने के कारण उन्होंने ईमानदारी से लिए गए 10,000 के ऋण की किश्त को भी समय पर चुकता कर दिया है। साथ ही पीएम स्वनिधि के तहत 20,000 रुपये (कैप्सूल 2) का ऋण के लिए भी आवेदन कर दिया है जो बैंक में प्रक्रियाधीन है। वह अपने व्यापार से बहुत खुश हैं और कोरोना के दौरान सहयोग के लिए सरकार व बैंक के भी आभारी हैं।

श्री अनिल कुमार सिन्हा अपनी चलंत दुकान के साथ।

मानगो नगर निगम में श्रमिकों को जॉब कार्ड प्रदान करते निगम के पदाधिकारी।

फुसरो नगर परिषद में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना दिवस पर हुआ टीकाकरण कैंप का आयोजन।

राज्य भर के नगर निकायों में हुआ 'मुख्यमंत्री श्रमिक योजना दिवस' का आयोजन

बड़ी संख्या में श्रमिकों से आवेदन प्राप्त कर जॉब कार्ड निर्गत किया गया

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के सभी नगर निकायों में दिनाक 14.08.2021 को "मुख्यमंत्री श्रमिक योजना दिवस" का आयोजन किया गया। इस मौके पर महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी के सम्मिलित प्रयास एवं दृढ़ निश्चय और पदाधिकारियों के मार्गदर्शन से नगर मिशन प्रबंधक, सामुदायिक संगठनकर्ता, सामुदायिक संसाधन सेवियों (CRPs) के द्वारा कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लाभुकों को सहृदय निमंत्रित किया गया।

जामताड़ा नगर पंचायत में भी हुआ आयोजन।

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रथम वर्षगांठ पर इस विशेष दिवस को राज्य के सभी नगर निकायों में दिनाक 14.08.2021 को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 'मुख्यमंत्री श्रमिक योजना दिवस' के रूप में मनाया गया। इस मौके पर महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी के सम्मिलित प्रयास एवं दृढ़ निश्चय और पदाधिकारियों के मार्गदर्शन से नगर मिशन प्रबंधक, सामुदायिक संगठनकर्ता, सामुदायिक संसाधन सेविकाओं (CRPs) के द्वारा कार्यक्रम का सफलपूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लाभुकों को आदरपूर्वक निमंत्रित किया गया। इस दौरान उन्हें 'मुख्यमंत्री श्रमिक योजना' के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। इस अवसर पर उपस्थित श्रमिकों को यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) के तहत नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत श्रमिकों को एक वर्ष में 100 दिनों का कार्य मुहैया कराया जाना है। वैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं एवं उनका मनरेगा जॉब कार्ड नहीं बना है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

'मुख्यमंत्री श्रमिक योजना दिवस' के मौके पर मानगो नगरनिगम क्षेत्र अंतर्गत कैंप लगाकर श्रमिकों का जॉब कार्ड बनाने के लिए उनके आवेदन जमा किए गए। साथ ही कोरोना के टीकाकरण कैंप का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जामताड़ा नगर पंचायत द्वारा भी कैंप लगाकर जॉब कार्ड आवेदन जमा किए गए। साथ ही श्रमिकों को जॉब कार्ड निर्गत किया गया। मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत कैंप लगाकर जॉब कार्ड आवेदन जमा किए गए। साथ ही श्रमिकों को जॉब कार्ड निर्गत किया गया। फुसरो नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत कैंप लगाकर जॉब कार्ड आवेदन जमा किए गए। इसके साथ ही श्रमिकों को जॉब कार्ड भी निर्गत किया गया। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना दिवस के अवसर पर सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में सामुदायिक संसाधन सेवियों (CRPs) के द्वारा वार्ड संख्या 1 से 11 में प्रचार-प्रसार करते हुए अकुशल श्रमिकों से जॉब कार्ड का आवेदन लिया गया एवं तैयार जॉब कार्ड का वितरण कार्यालय सभाकक्ष में किया गया। इस दौरान नगर पंचायत कार्यालय में अकुशल श्रमिकों को बुलाकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के उद्देश्य, जॉब कार्ड हेतु पात्रता एवं उसे बनाने की प्रक्रिया तथा योजना के तहत किए जाने वाले कार्य एवं कार्य आवंटन की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में उपस्थित अकुशल श्रमिकों को कोरोना टीकाकरण से संबंधित जानकारी दी गई। इसके साथ ही इस मौके पर विशेष टीकाकरण कैंप लगाकर 80 लोगों को कोरोनारोधी टीका भी लगाया गया। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में लातेहार नगर पंचयात कार्यालय में कैंप लगाकर जॉब कार्ड आवेदन जमा किए गए, जॉब कार्ड वितरित व जॉब कार्ड आवंटित भी किए गए। इस दौरान मिहिजाम नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) में निबंधित श्रमिकों के बीच जॉब कार्ड का वितरण भी किया गया।

मिहिजाम नगर परिषद की तस्वीर।

असहाइ आर बेबस रूपमणि के मिललइ मुख्यमंत्री श्रमिक योजना से जीएक सहारा

लातेहर शहर से दूर सांसग, सिकनी कोलियरी माइंस चंदवा के रहे वाली बेबस लाचार रूपमणि कुमारी (बाप स्व० किशोर भुंइया) के माइ बाप अब ई दुनिआएँ नाँए। एगो बड़ भाई के सहारा भी नाँए रहल ओहो ए दुनियां में नाएँ रहल एक भाई हइओ हइ उ ओकरा नाँय माने। ई हालत से बेबस होक, अपन रोजी-रोटी जुगाड़ करे लए लातेहार शहर आइ गेल। रेजा कुली काम करे लागल, माकिन रोज-रोज काम नाँए मिले से खाइ पीएम दिकत होओ लागल। डेराएँ एको अन के दान नाँए, इसने में जान-पहचान डोम टोली चंदन डीह के विवेक राम के बेटी प्रिया से भेल उ ओकरा अपन घरें ले आइएल।

माकिन ई का एकरा बेस लखे खाएलपीएल भी नाँए मिलोलगल आर घरेक खुबे काम करावल जायलगल ।

एक रोज ओकरा एक बेसहारा जेनी पूनम देवी से भेंट भेल ओकरो मरद छोड़ के भाइग गेल हइ। दुगो छोटे-छोटे छुआ हथ, ओकरो छउआ के पाले पोसेक समसया, एहे समस्या उबरे खातिर काम धाम खोजेक बेराएँ। रूपमणि से भेंट भइ गेल। एके रकम समस्या वाला के अपने जोड़ी पारी से दोस्तीओ भी हो जा हइ। एक रोज पूनम देवी के सीआरपी दीदी नगर पंचायत लतेहार में काम के बारें बतेलेहल्थ। बस दुनु आफिस काम मंगेले आफिस आ गेला। हिंआ सीएमएम आनन्द किशोर दाँगी जी से भेट भेइल। ई सब भूखे पिआसे आफिस आइल हेला। उ आपन पॉकेट से कुछ रुपिया देलका आर बगल के दुकान में भेजदेलका तब तक आधार, बैंक के पासबुक आरो आरो कागज ले लेलका। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में जॉब कार्ड बना देवल गेल आर कार्यपालक पदाधिकारी हांथे बाट देलका। इनखा न दिन के साफ-सफाई काम मे लगा देलका। दुनु रोज-रोज काम करो लागला। आज बड़ी खुस हथ ई खातिर की काम खातिर रोज रोज कन्हु नाँए भटके परे। योजना चलवइआ मुख्यमंत्री जी के हृदय से आभार दे लका।

जॉब कार्ड प्रदान करते लातेहार के सीएमएम।

खोरठा भाषा में अनुवाद:-डॉ आनन्द किशोर दाँगी
सिटी मिशन मैनेजर, लातेहार नगर पंचायत।

जेएनएसी की नई पहल : प्रदूषणमुक्त होगा जमशेदपुर शहर

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय में 15वें वित्त आयोग के तहत एक अहम बैठक आयोजित कर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए आवंटित राशि के खर्च करने पर चर्चा हुई। इसमें तय हुआ कि शहर में दो बायो सीएनजी प्लांट लगेगा। बायो सीएनजी यानि गीले कचरे से सीएनजी गैस उत्पादन का प्लांट लगाने की तैयारियों पर चर्चा की गयी। बैठक में निगम के पदाधिकारी के साथ-साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक डीसी सिंह एवं तौफीक असलम भी मौजूद थे।

शहर में गोबर और कचरे से (बायो सीएनजी यानि गीले कचरे से) सीएनजी गैस उत्पादन का दो प्लांट लगेगा। सोनारी मरीन ड्राइव में लगने वाले दोनों प्लांट की क्षमता 50-50 टन की होगी। इस प्लांट को स्थापित करने वाली कंपनी ही इसका ऑपरेशन व मेंटेनेंस भी करेगी। बायो सीएनजी प्लांट लगाने के लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। घरेलू कचरों से गैस और नेचुरल खाद भी बनाया जाएगा। इस गैस का उपयोग ऑटो एवं बसों को चलाने में भी होगा। प्लांट संचालित करने वाली कंपनी सीएनजी वाहनों को तय कीमतों के अनुसार गैस बेचेगी। शहर की सिटी बसों में भी इसी गैस का उपयोग होगा।

शहर में बहुत जल्द लगेंगे दो सीएनजी गैस प्लांट

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण।

नेशनल क्लीन एयर कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में यह पहल की जा रही है। शहर में अगले छह माह में सभी ऑटो को सीएनजी करने की तैयारी चल रही है। शहर के ऑटो संचालकों के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी ने पहले ही बैठक कर एसोसिएशन को सभी ऑटो को सीएनजी में तब्दील कराने को कहा है।

एएक्यूएमएस सिस्टम की होगी स्थापना

जेएनएसी के पदाधिकारियों ने कहा है कि शहर की हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए ड्रोन मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जगह-जगह एएक्यूएमएस सिस्टम की स्थापना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में की जाएगी।

प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति

सीएनजी प्लांट स्थापित होने से कचरे के प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। सीएनजी से वाहनों के लिए स्वच्छ इंधन भी प्राप्त हो सकेगा। बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के टीम के अलावा जमशेदपुर अक्षेस के प्रयासों एवं भविष्य कार्य योजना से पूर्ण संतुष्ट नजर आयी।

ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध होंगे 'सोनचिरैया' ब्रांड के प्रोडक्ट

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बनाये गये सामान के लिए 'सोनचिरैया' नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया है

पेड़किया /गुजिया बनाकर दिखाती नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव (बीच में) व स्वयं सहायता समूह की महिलाएं।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं द्वारा बनाए सामान अब फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी मिलेंगे। प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तकरघा उत्पाद सहित रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े उत्पादों की बिक्री अब ऑनलाइन भी होगी। इससे झारखंड की महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच मिलेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने इसे 'सोनचिरैया' का ब्रांड नाम दिया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने में सहायता करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।

राँची नगर निगम द्वारा अब तक इस कार्य के लिए 25 ग्रुप को अमेजन व फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड किया जा चुका है। आनेवाले दिनों में 30 और ग्रुपों को जोड़ने की तैयारी है। राँची नगर निगम की डे-एनयूएलएम शाखा द्वारा 2119 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। हर ग्रुप में 10 से 20 महिलाओं को जोड़ा गया है। ग्रुप विभिन्न प्रकार के सामान का उत्पादन कर सके, इसके लिए उन्हें रिवाल्विंग फंड के रूप में 10 हजार की राशि के अलावा ट्रेनिंग भी दी गई है। ट्रेनिंग के बाद जिन ग्रुपों का रिकॉर्ड अच्छा था, उन्हें बैंक से लोन उपलब्ध करवाया गया है। गौरतलब है कि कोरोना काल में बहुत सारे समूहों की गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई थीं, मगर अब एक बार फिर से सारे ग्रुपों को सक्रिय कराया जा रहा है ताकि वे घर बैठे ही अपने उत्पादों का निर्माण कर सकें।

इनके उत्पादों को बेहतर कीमत मिले, इसके लिए इन्हें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी उपलब्ध करवाया गया है।

लांचिंग से पहले उत्पादों की हुई जांच

ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में लांचिंग से पहले अमेजन व फ्लिपकार्ट द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की अच्छे तरीके से जांच की गई। जांच के दौरान यह देखा गया कि वे उत्पाद सही में संबंधित समूहों द्वारा बनाए गए हैं या नहीं। जांच में पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद सारे उत्पादों की फोटोग्राफी की गई। फिर इसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर डाला गया।

ग्रुप की महिलाएं बना रही हैं विभिन्न सामान

नारियल छिलका से इंब्रायडरी मास्क, खिलौने, मशरूम, जूट बैग, दीवाली के लिए स्पेशल दीये, एलइडी बल्ब सहित घर की सजावट के लिए वंदनवार, आर्टिफिशियल फ्लावर, वूलन शाल, डोर मेट, नेकलेस, लटकन, डिजाइनर ब्लाउज, इयर रिंग, बाली व झूमका, चाबी रिंग, मंगलसूत्र सहित कई प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं।

'सोनचिरैया' ब्रांड के तहत पेड़किया की भी हुई लांचिंग

शहरी क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व उनके हुनर की ब्रांडिंग के लिए झारखण्ड सरकार ने नई पहल की है। इस कड़ी में राजधानी राँची में 'सोनचिरैया' ब्रांड के नाम से गुजिया और पेड़किया की लांचिंग की गई। नगरीय प्रशासन निदेशालय के तत्वावधान में 25 अगस्त 2021, दिन बुधवार को इसकी विधिवत शुरुआत की गई। निदेशालय की निदेशक विजया जाधव की उपस्थिति में बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों ने पूजा-अर्चना के साथ शुद्धता को बरकरार रखते हुए शुद्ध घी और खोआ से पेड़किया का उत्पादन शुरू किया। इस दौरान महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए खुद डीएमए निदेशक भी गुजिया बनाती हुई दिखीं। इस मौके पर डीएमए निदेशक ने बताया कि दीनदयाल अंत्योदय-शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) योजना के तहत सरकार का यह प्रयास है कि इन महिलाओं का आर्थिक संवर्धन हो। अब इनके द्वारा निर्मित उत्पाद बाजार तक आसानी से पहुंचेगा। इस उत्पाद का ब्रांड नाम होगा 'सोनचिरैया' जो केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।

वस्तुओं का निर्माण करतीं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं।

गुजिया बनाकर दिखातीं डीएमए की निदेशक विजया जाधव (बीच में)।

विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करतीं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं।

स्वतंत्रता दिवस पर गृह प्रवेश के साथ पीएम आवास के लाभुकों ने मनाया आजादी का जश्न

राज्य के सभी नगर निकायों में हुआ गृह प्रवेश का कार्यक्रम

इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित पूर्ण आवासों के लाभुकों का गृह प्रवेश करवाया गया। यह शुभ कार्य नगरीय प्रशासन निदेशालय (डीएमए) के निर्देश पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर कई नगर निकायों में गृह प्रवेश के पूर्व नए घर को फूल एवं बैलून से सजाया गया। इस दौरान मानगो नगर निगम, धनबाद नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, लोहरदगा नगर परिषद, सिमडेगा नगर परिषद, चाकुलिया नगर पंचायत, छत्तरपुर नगर पंचायत, बासुकिनाथ नगर पंचायत, बरहरवा नगर पंचायत, मधुपुर नगर परिषद, झुमरीतिलैया नगर परिषद, साहिबगंज नगर परिषद और बुण्डू नगर पंचायत आदि क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभुकों का गृह प्रवेश करवाया गया। साथ ही साथ साथ ही साथ कई नगर निकायों में लाभुकों के नए आवास के सामने वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। मानगो नगर निगम क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर लाभुकों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलना नगर निकायों की एक अच्छी पहल है। इस मौके पर उन्होंने लाभुकों से आवास योजना के तहत निर्मित अपने नए मकान को हमेशा स्वच्छ, सुंदर व साफ रखने की सलाह दी। गौरतलब है कि मानगो नगर निगम अंतर्गत अबतक 740 आवास में से 70 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए लाभुकों को उपलब्ध कराया गया है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तरपुर नगर पंचायत में भी हुआ गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन।

पीएम आवास योजना के तहत कुष्ठ रोगियों को जल्द मिलेगा अपना आशियाना

जमशेदपुर में आयोजित डीएमए निदेशक की समीक्षा बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर टाटा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहमति जताई

टाटा कंपनी राज्य सरकार के साथ मिलकर कुष्ठ रोगियों के लिए जमशेदपुर के देव नगर में स्थित नवजीवन कुष्ठ आश्रम में बन रहे पीएम आवास (शहरी) के लिए अपना अंशदान देगी ताकि उन्हें निःशुल्क आवास मुहैया कराई जा सके। गौरतलब है कि पीएमवाई (यू) के घटक 3 के तहत देवनगर कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ रोगियों के लिए 400 पीएम आवास का निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से 240 आवास का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। आवास की लागत लगभग 6.5 लाख रुपये है, जिसमें से 2.5 लाख का अंशदान सरकार दे रही है। 4 लाख रुपये लाभुक को देना होता है। चूंकि लाभुक कुष्ठ रोगी व गरीब हैं। इस कारण वह चार लाख रुपये खुद वहन नहीं कर सकते। ऐसे में विभाग ने लाभुकों को मुफ्त में आवास उपलब्ध कराने का नया रास्ता निकाला है। विभाग की पहल पर अब इस राशि का भुगतान टाटा कंपनी अपने सीएसआर (कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी) तहत सहयोग के रूप में करने जा रही है। इस संबंध में दिनांक 27 अगस्त, 2021 को नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के सभागार में पीएम आवास समेत अन्य योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में टाटा कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया गया था, जिन्होंने विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। इस बैठक में नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक ने जमशेदपुर अक्षेस, आदित्यपुर नगर निगम एवं मानगो नगर निगम में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यों के संबंध में भी जानकारी ली। निदेशक ने सभी संबंधित अधिकारियों, नगर प्रबंधकों एवं नगर मिशन प्रबंधकों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत शहरी श्रमिकों का जॉब कार्ड बनाते हुए नगर निकायों में संचालित योजनाओं व अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर उन्हें अकुशल श्रमिकों के रूप में काम दिलाने का निर्देश भी दिया।

अधिकारियों के साथ बैठक करती नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव।

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) से बदल रही हजारीबाग शहर की तस्वीर

रोजगार के साथ-साथ शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था में भी हो रहा बदलाव

एक तरफ जहां राज्य सरकार द्वारा पिछले साल शुरू की गई मुख्यमंत्री श्रमिक योजना झारखण्ड के प्रवासी मजदूरों व अकुशल श्रमिकों को साल भर में 100 दिन का रोजगार मुहैया करवा कर उन्हें कोरोना संकट के कारण हुए आर्थिक नुकसान से उबारने का प्रयास कर रही है, वहीं इस योजना से प्रदेश के कई शहरों की तस्वीर भी बदल रही है। हजारीबाग शहर भी इनमें से एक है।

हजारीबाग नगर निगम में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) के तहत 600 से अधिक श्रमिकों का निबंधन किया गया है तथा उन श्रमिकों को नगर निगम के द्वारा जॉब कार्ड भी प्रदान कर दिया गया है। मांग के आधार पर इन जॉबकार्डधारी श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

वर्तमान में हजारीबाग शहरी क्षेत्र में मुख्य नालों की सफाई का कार्य मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) के तहत निबंधित मजदूरों से करवाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत अगस्त माह के पहले सप्ताह में ही हुई है। इसके पूर्व निगम क्षेत्र में अवस्थित तालाबों एवं झील की सफाई के कार्य में भी इस योजना के तहत मजदूरों को लगाया गया था। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में निगम के अधीन संचालित अन्य योजनाओं में भी इन जॉब कार्डधारी श्रमिकों को रोजगार दिलाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दरअसल, अब मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना से गांवों से आने वाले मजदूरों को भी जोड़ा जा रहा है। गांव से आकर शहर में काम करने वाले मजदूर इस योजना के तहत नगर निगम में अपना निबंधन करवाकर काम की मांग कर सकते हैं। इस योजना के तहत अब उनके नाम का जॉब कार्ड भी जारी हो सकेगा। यानि काम के अभाव में राज्य के श्रमिकों को खाली बैठना न पड़े। उन्हें हरसंभव रोजगार मिल सके, यही मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का मुख्य मकसद है। हजारीबाग शहर में स्थित मल्लाह टोला में निमार्णाधीन बड़े नाले की सफाई के कार्य की शुरुआत भी मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) के तहत की गई है। इससे पहले शहर के खजांची तालाब की साफ-सफाई भी इसी योजना के तहत मजदूरों द्वारा कराई गई तथा उसे एक नया रूप दिया गया है। साफ-सफाई के बाद इस तालाब का जल अब स्वच्छ और निर्मल हो गया है।

हजारीबाग झील की सफाई करते मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में निबंधित श्रमिक।

> (MSY) के तहत मजदूरों को हजारीबाग झील को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम दिया गया है। नगर निगम के अलावा अन्य विभागों में भी चलने वाली योजनाओं में मजदूरों से काम लिया जाएगा।

PM आवास योजना के तहत 25,000 रुपये जीतने का मौका

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 'खुशियों का आशियाना' प्रतियोगिता का आयोजन

सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रचार-प्रसार और जागरूकता के लिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण पहल की गई है। दरअसल, विश्व के सबसे बड़े किफायती आवास मिशनों में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ने अनूठी पहल करते हुए 'खुशियों का आशियाना' नामक लघु फिल्म प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा 25 जून, 2021 को पीएमएवाई(यू) योजना की छठी वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी।

इस पहल को चुनौती और कंपीटिशन मोड में लागू किया जा रहा है और यह पहल भारत सरकार के 75 वर्षों के प्रगतिशील भारत और उसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धि के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए कार्यक्रम 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में प्रस्तावित अन्य कई कार्यक्रमों में से एक हैं. इसके लिए एक एसओपी (SOP) पहले ही जारी की जा चुकी है।

राज्य व देश स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता को 'खुशियों का आशियाना' नाम दिया गया है। इस फिल्म की अवधि सिर्फ 3 मिनट की होगी। इस प्रतियोगिता के विजेता को प्रथम पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 20 हजार रुपये तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 12,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस फिल्म में प्रधानमंत्री आवास (शहरी) के निर्माण के बाद इसके लाभुकों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ उनकी जीवनशैली एवं आत्मविश्वास में बदलाव को लेकर एवं संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए अतिलघु फिल्म बनाया जाना है। यह प्रतियोगिता पिछले एक जुलाई से प्रारंभ हुई है जो 15 सितंबर 2021 तक चलेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित आवासों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाना है।

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर बनेगी फिल्म

इस प्रतियोगिता में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक, छात्र, युवा, सिविल सोसाइटी के सदस्य, गैर सरकारी संस्थान के कर्मचारी, कोई भी संस्था जो नगर निगम से जुड़ा हुआ नहीं हो, 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति और व्यवसायिक फोटोग्राफर भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट फिल्म में यह दिखाना होगा कि इस योजना ने किस तरह से लोगों का जीवन प्रभावित किया है और इससे लोगों का जीवन कितना बेहतर हुआ है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पीएमएवाई के वेबसाइट https://pmay-urban.gov.in/, पीएमएवाई-यू मोबाइल ऐप पर पंजीकरण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अपने लाभार्थियों के साथ जुड़ने और सभी हितधारकों के साथ काम करने की लगातार कोशिश करता है। इस योजना के जरिए उन लोगों की कहानी सामने लाने की कोशिश की जा रही है जिनका जीवन प्रधानमंत्री आवास योजना से खुशहाल हुआ है।

नगरीय प्रशासन निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार का प्रकाशन

ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर : गढ़वा नगर परिषद

ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मशहूर होने के साथ-साथ गढ़वा को प्रकृति ने भी बहुत कुछ दिया है। इस बात का एहसास किसी भी नए व्यक्ति को गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही आनंदित कर देता है। नगर परिषद का क्षेत्र बिहार, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश की सीमा के काफी करीब है। इस वजह से इन तीनों राज्यों के लोगों का व्यावसायिक उद्देश्य से यहां आना-जाना लगा रहता है। यही कारण है कि भविष्य में पूरे गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के विकास की असीम संभावनाएं बरकरार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में गढ़वा झारखंड के प्रमुख शहरों की फेहरिस्त में शुमार हो जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा शहर के विकास के लिए जारी कार्य इस बात की पूरी तरह से गवाही दे रहे हैं। गौरतलब है कि गढ़वा नगर परिषद की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी।

कुल क्षेत्रफल	कुल वार्डों की संख्या	कुल जनसंख्या	
12.46 वर्ग किलोमीटर	21	46,059	पुरुष : 24,342 महिला : 21,717

अध्यक्षः श्रीमती पिंकी केशरी उपाध्यक्षः श्रीमती मीरा पांडे कार्यपालक पदाधिकारीः श्री संजय पांडे

गढ़वा नगर परिषद एक नजर में

» मुख्य पर्यटन स्थल

- राधा कृष्ण मंदिर, नगरऊंटारी
- सुखलधरी जल प्रपात, धुरकी
- सतबहिनी जल प्रपात, गढ़वा
- दानरो डैम, गढ़वा
- खजूरी डैम

» प्रमुख खनिज

- डोलोमाइट
- लाइमस्टोन ग्रेफाइट
- चाइना क्ले और ग्रेनाइट।

नगर परिषद में कुल वार्डों की संख्या 21 है, जिनमें से 17 महिला वार्ड पार्षद शामिल हैं। खास बात यह भी है कि इसके अलावा नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पदों पर भी महिला ही आसीन हैं। अबतक नगर परिषद के तीन चुनाव हुए हैं। नगर परिषद क्षेत्र के विकास के लिए खाका तैयार किया गया है, जिसके अनुरूप पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्य भी संचालित किए जा रहे हैं।

गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना प्रमुख रूप से शामिल हैं। डे-एनयूएलएम के तहत शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का गठन कर गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा गढ़वा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए 15 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित टाइड ग्रांट की राशि से विभिन्न उपकरणों के क्रय के लिए नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। इनकी खरीददारी 7.27 करोड़ की लागत से की जाएगी। इन उपकरणों के उपलब्ध होने के बाद शहर की सफाई आटोमेटिक मशीनों द्वारा होगी। साथ ही नागरिकों को चलंत शौचालय व स्टेनलेस स्टील वाटर टैंकर की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। जबकि नाला क्लीनिंग मशीन, रोड स्वीपिंग मशीन, रोड रोलर, सेनिटाइजेशन स्प्रेयर मशीन, सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन भी मंगाए जाएंगे।

''आवास पर संवाद'' कार्यक्रम के तहत ''समावेशी आवास'' विषय पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन

अपना खुद का घर होना सभी का सपना होता है। गरीबी और मुफलिसी के बीच जीने वाले लोगों के इसी सपने को पूरा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) चला रही है। केवल गांव ही नहीं, शहरों में भी इस योजना के जरिये आर्थिक कमी से जूझ रहे लोगों को किफायती आवास मुहैया कराए जा रहे हैं।

सरकार के द्वारा योजना के प्रति जन जागरूकता और प्रचार-प्रसार के लिए पहल करते हुए 25 जून, 2021 को PMAY(U) योजना की छठी वर्षगांठ के अवसर पर ''आवास पर संवाद'' कार्यक्रम की घोषणा की गयी थी। इसके अंतर्गत 75 सेमिनारों और कार्यशालाओं की श्रृंखला में 'सभी के लिए आवास' पर चर्चा किया जाना सुनिश्चित किया गया था।

''आवास पर संवाद'' कार्यक्रम के तहत स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली में दिनांक 19.08.2021 को ''समावेशी आवास'' विषय पर एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बतौर विशेष अतिथि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा एवं अन्य सम्मानीय मेहमान सम्मलित हुए। इस ऑनलाइन सेमिनार में झारखण्ड के नगर निकायों के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुड़े पदाधिकारियों ने भाग लिया एवं कार्यशाला का लाभ उठाया। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने बढ़ती शहरी आबादी को समायोजित करने के लिए किफायती, रहने योग्य और सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस घरों वाले शहरों का विकास करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि अपने बेहतर भविष्य के लिए शहरों में आने वाले शहरी श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों और अन्य गरीब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें उनके लिए सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस घर बनाने चाहिए ताकि झुग्गी-झोपड़ियां खत्म हों और मौजूदा झुग्गी-झोपड़ियों के स्थान पर सर्व-समावेशी आवासों के विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते आवास एवं शहरी मामलों के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा।

संरक्षक
श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री

संपादक
विनय कुमार चौबे
सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

कार्यकारी संपादक
विजया जाधव
निदेशक
नगरीय प्रशासन निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास विभाग

यह बुलेटिन विभाग के कार्यों के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित है।

नगरीय प्रशासन निदेशालय (डीएमए) व जेएसएलपीएस के संयुक्त तत्वावधान में DAY-NULM योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगर निकायों के कुल 364 सामुदायिक संसाधन सेवियों (CRPs) के 11 अलग-अलग बैचों में "तीन दिवसीय आवासीय उन्मुखीकरण सह स्क्रीनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन दिनांक 11.08.2021 से 26.08.2021 तक राजधानी राँची के तीन विभिन्न स्थानों पर किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया तथा उन्हें सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं।

नगरीय प्रशासन निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Follow us on : @JharkhandDMA , Website : dmajharkhand.in

1st Floor, JUPMI Building, Beside H.E.C Headquarter, Dhurwa, Ranchi -834004, Jharkhand